Neutral Citation
2020:CGHC:10993-DB

एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
2019 का FAM नंबर 99

- पवन कश्यप पुत्र स्वर्गीय कृष्ण कुमार कश्यप उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी टुटेजा फर्निचर के पीछे तेलीपारा रोड, पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली तहसील और जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, जिला: बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

---- अपीलार्थी/अनावेदक

बनाम

- श्रीमती सोनी कश्यप @ लल्ली कश्यप पत्नी श्री पवन कश्यप, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी कुम्हारपारा स्कूल के पास, कर्बला, रोड, तहसील और जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़, नाबालिग बच्चों के प्राकृतिक संरक्षक कान्हा @ वासु कश्यप, उम्र लगभग 06 वर्ष और बेटी कैशर @ श्रियांशी कश्यप, उम्र 06 वर्ष, दोनों पवन कश्यप के बच्चे हैं, निवासी टुटेजा फर्निचर के पास, तेलीपारा, रोड, तहसील और जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ बिलासपुर, छत्तीसगढ़
-

---- प्रतिवादी/आवेदक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता के लिए: श्री मनोज परांजपे और श्री के. रोहन, वकील
प्रतिवादी के लिए: श्री पराग कोटेचा, वकील

डी.बी.: माननीय श्री न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
माननीय श्रीमती जस्टिस विमला सिंह कपूर
सीएवी निर्णय

प्रति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, जे.

29/06/2020

1. यह अपील अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर द्वारा सिविल एमजेसी क्रमांक 03/2018 में पारित दिनांक 15-03-2019 के विवादित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध है, जिसके द्वारा विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने नाबालिग पुत्र कान्हा उर्फ

बासु कश्यप एवं पुत्री केशर उर्फ श्रेयांशी कश्यप की अभिरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिवादी-मां के आवेदन को स्वीकार कर लिया है।

2. प्रत्यर्थी सोनी कश्यप ने अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (संक्षेप में "1890 का अधिनियम") की धारा 6, 7 एवं 8 के अंतर्गत कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर में अपने नाबालिग पुत्र कान्हा उर्फ बासु कश्यप, उम्र 8 वर्ष एवं पुत्री केशर उर्फ श्रेयांशी कश्यप, उम्र 6 वर्ष को अभिभावक नियुक्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी का विवाह अपीलार्थी से हुआ है तथा उनके विवाहेतर संबंध से 01-11-2007 को पुत्र का जन्म हुआ तथा उसके पश्चात् 09-11-2009 को पुत्री का जन्म हुआ। प्रत्यर्थी-माता के अनुसार अपीलार्थी-पिता शराबी है तथा दहेज की मांग के नाम पर उसे परेशान करता था तथा मारपीट करता था। दिनांक 24-05-2014 को प्रत्यर्थी को बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसे चोटें आई तथा उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय बच्चे मायके में थे, लेकिन अपीलकर्ता दादी से मिलाने के नाम पर बेटी श्रेयांशी को ले गया। थाने में रिपोर्ट होने पर दोनों पक्षों के बीच काउंसलिंग कराई गई तथा अपीलकर्ता द्वारा उचित देखभाल करने का आश्वासन दिए जाने पर प्रत्यर्थी-मां पुनः ससुराल आ गई। लेकिन अपीलकर्ता ने पहले की गतिविधियां जारी रखी, इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर पुनः ससुराल चली गई। यह भी दलील दी गई कि अपीलकर्ता ने अपने बेटे को कहीं छिपा दिया है, जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी को नहीं है। दिनांक 21-07-2015 को अपीलकर्ता ने अपने पिता लखन लाल के साथ मारपीट की तथा बेटी को छीन लिया, जिसके संबंध में भी थाने में रिपोर्ट की गई, तब से बच्चे अपीलकर्ता-पिता के पास हैं। आगे यह दलील दी गई कि अपीलकर्ता के बड़े भाई की पत्नी भी अपने साथ हुई क्रूरता के कारण अपना ससुराल छोड़ कर चली गई है और घर में केवल अपीलकर्ता, उसका बड़ा भाई और वृद्ध बीमार मां ही रह गए हैं। अपीलकर्ता-पिता और उसका बड़ा भाई शराबी हैं और वे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और इसलिए परिवार में सक्षम महिला सदस्य के अभाव में बच्चों की उचित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

देखभाल और देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं है। वैवाहिक घर का समग्र वातावरण बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, विकास और देखभाल के लिए अनुकूल नहीं है। प्रत्यर्थी-माता एक शिक्षित महिला है। अपीलकर्ता-पिता प्रत्यर्थी-माता को बच्चों से मिलने नहीं दे रहे हैं। वाद का कारण 19-06-2014 और 21-07-2015 को उत्पन्न हुआ, जब बच्चों को छीन लिया गया और प्रत्यर्थी-माता को उसके बच्चों से वंचित कर दिया गया।

3. अपीलार्थी-पिता द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन में लगाए गए आरोपों का खंडन किया गया तथा बताया गया कि प्रतिवादी-माता का पैतृक घर स्थानीय होने के कारण प्रतिवादी-माता अक्सर अपने पैतृक घर आती-जाती रहती है तथा वहीं रहती है। बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया गया है तथा अपीलार्थी-पिता बच्चों की समुचित देखभाल कर रहे हैं तथा उन्हें उचित शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तथा उनकी शिक्षा का समस्त व्यय स्वयं उठा रहे हैं। जहां तक प्रतिवादी-माता के शरीर पर चोट का प्रश्न है, गिरने के कारण उसे चोट लगी है। प्रतिवादी-माता ससुराल छोड़कर चली गई है तथा वह वापस नहीं आ रही है, तत्पश्चात दिनांक 23-06-2014 को प्रतिवादी-माता को पंजीकृत नोटिस दिया गया, इसके बावजूद भी वह वापस नहीं आई। अपीलार्थी-पिता ने बताया है कि वह अभी भी अपनी पत्नी को अपने साथ रखने को तैयार है, लेकिन प्रतिवादी-माता मामूली विवाद के कारण अपने ससुराल वापस नहीं आ रही है। थाने में की गई रिपोर्ट झूठी है। घरेलू हिंसा से उत्पन्न मामले में अंतरिम भरण-पोषण का आदेश अंततः अपीलकर्ता-पिता के पक्ष में है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षों की दलीलों के आधार पर विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने यह मुद्दा तय किया कि क्या बच्चों की अभिरक्षा माँ को देना उनके सर्वोत्तम हित में है। अपने मामले के समर्थन में प्रतिवादी-माँ ने खुद की जाँच की है। अपीलकर्ता-पिता ने खुद की और एक अन्य गवाह की जाँच की। दोनों पक्षों ने दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए।

विद्वान कुटुम्ब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद, बच्चों के सर्वोत्तम हित में पिता के स्थान पर माँ को अभिरक्षा देना होगा। यह वह आदेश है, जिसे इस अपील में चुनौती दी गई है।

5. विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित किए गए विवादित निर्णय और डिक्री की वैधता और वैधता पर सवाल उठाते हुए अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने इस निष्कर्ष पर पहुंचते समय दलीलों और साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नहीं किया है कि बच्चों का कल्याण मां के हाथों में होगा। यह तर्क दिया गया है कि पक्षकार हिंदू विधि द्वारा शासित हैं और इसलिए हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (संक्षेप में "1956 का अधिनियम") की धारा 6 के तहत निहित प्रावधानों के तहत, यह पिता है, जो हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक संरक्षक है। वर्तमान मामले में, दोनों बच्चे पांच वर्ष से अधिक उम्र के थे, और इसलिए, पिता ने कानूनी रूप से बच्चों की अभिरक्षा रखने के अधिमान्य अधिकार का आनंद लेने के लिए मान्यता प्राप्त की, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता कि इस तरह की अभिरक्षा की अनुमति देना बच्चों के हित और कल्याण में नहीं होगा। यह तर्क दिया गया है कि अन्यथा साबित करने का भार माँ पर है। केवल इसलिए कि बच्चे 8 और 6 वर्ष के हैं, विधायी विवेक के विरुद्ध, यह नहीं माना जा सकता कि नाबालिग बेटे और बेटी के संबंध में माँ बेहतर अभिभावक होगी। जब तक माँ इस बात के पुख्ता सबूत नहीं देती कि बच्चों के कल्याण और हित पर उन्हें पिता की अभिरक्षा में जारी रखने की अनुमति देने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, माँ नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा का अधिमान्य दावा नहीं कर सकती। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क यह है कि स्थापित कानूनी स्थिति के मद्देनजर कि यह बच्चे का कल्याण है, जिसे सर्वोपरि माना जाना चाहिए, दलीलें और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत अपरिहार्य निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि बच्चों का कल्याण पिता के हाथों में है। अपीलकर्ता-पिता न केवल आर्थिक रूप से सक्षम है, बल्कि वह बच्चों के समग्र विकास के लिए सभी आवश्यक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

देखभाल और सावधानी भी बरत रहा है। यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए गए हैं कि बच्चों को स्कूल में उचित शिक्षा मिल रही है और उनके घर में मानसिक आराम और संगति सहित उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अपीलकर्ता की माँ बच्चों की पूरी देखभाल करने में सक्षम है, जो भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हुए हैं। आगे यह भी कहा गया है कि नीचे के विद्वान न्यायालय ने प्रतिवादी-माँ की वित्तीय क्षमता को अनुचित महत्व दिया है, जो अपीलकर्ता-पिता की क्षमता के लगभग बराबर है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश का मुख्य जोर इस बात पर रहा है कि प्रतिवादी-मां अपीलकर्ता-पिता की तुलना में अधिक सक्षम है, जो 1956 के अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रासंगिक वैधानिक अधिदेश की अनदेखी करता है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि मां को अभिरक्षा प्रदान करके अभिभावक की नियुक्ति का आदेश पारित करने से पहले 1890 के अधिनियम की धारा 17 (3) और धारा 17 (5) के अधिदेश का पालन न करने में नीचे के विद्वान न्यायालय ने गंभीर अवैधता की है। बच्चों की इच्छाओं का पता नहीं लगाया गया था और भले ही ऐसी विशिष्ट प्रार्थना की गई थी, अप्रासंगिक विचार पर, 06-10-2016 को पारित अवैध आदेश द्वारा ऐसी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया था। बच्चों की इच्छा का पता लगाए बिना, बिना किसी ठोस सबूत के कि पिता उपयुक्त नहीं है, माँ के पक्ष में अभिरक्षा का आदेश पारित करना भी अधिनियम 1956 की धारा 6 का उल्लंघन है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण और मूल्यांकन नहीं किया है, बल्कि बिना उचित जांच के और पक्षों के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास करने या न करने का कोई कारण बताए बिना यंत्रवत् विचार किया है और इसलिए, आरोपित निर्णय आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के तहत निहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि शुरू से ही, बच्चे केवल पिता के पास हैं और सबूत साबित करते हैं कि बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे थे, जहाँ उन्हें उनके पिता ने भर्ती कराया था न कि उनकी माँ ने, जैसा कि प्रतिवादी-माँ ने दावा किया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि बड़े भाई की अशांत वैवाहिक स्थिति के बारे में अप्रासंगिक विचार को ध्यान में रखा गया है। अपीलकर्ता के शराबी होने संबंधी कथन पर विश्वास किया गया है बिना किसी पुख्ता सबूत के अपने कथन के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **धनवंती जोशी बनाम माधव अंडे, शीला बी. दास बनाम पी.आर. सुगाश्री**[1] , **निल रतन कुंडू और अन्य बनाम अभिजीत कुंडू**[2] , **गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल**[3], **अंजलि कपूर (एसएमटी) बनाम राजीव बैजल**[4], **विष्णु एवं अन्य बनाम जया**[5], **शालीन काबरा बनाम शिवानी काबरा**[6] **एवं जीतेन्द्र अरोड़ा एवं अन्य बनाम सुकृति अरोरा एवं अन्य**[7] का अवलंब लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी-मां के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि कुटुम्ब न्यायालय ने पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की बहुत ही सावधानीपूर्वक और विस्तृत जांच की है और साक्ष्यों की सूक्ष्म जांच और संयोजन के बाद, यह निष्कर्ष निकाला है कि बच्चों का कल्याण मां को अभिरक्षा देने में निहित है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मामले का फैसला करते समय, विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 सीपीसी द्वारा अनिवार्य कोई कारण नहीं बताया है। अगला तर्क यह है कि जहां तक1956 के अधिनियम की धारा 6 के तहत पिता के वैधानिक अधिकार का संबंध है, यह पूर्ण नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक बार यह पाया जाता है कि बच्चों का कल्याण और उनका सर्वोत्तम हित मां को अभिरक्षा देने में निहित है, 1956 के अधिनियम की धारा 6 के तहत वैधानिक अधिकार बच्चों के कल्याण के विचार के लिए झुकना होगा। उन्होंने आगे कहा कि विद्वान न्यायालय ने न केवल दोनों पक्षों की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखा है, बल्कि अन्य प्रासंगिक विचारों को भी ध्यान में रखा है और बेहतर वित्तीय स्थिति, माँ का अधिक शिक्षित होना, माँ के पैतृक घर में बेहतर परिवेश और माहौल होना, पिता का कम शिक्षित होना, कम आय होना और पिता के घर में पारिवारिक माहौल बच्चों के समुचित विकास के

लिए अनुकूल न होना, आंतरिक विवाद और बूढ़ी दादी का घर पर होना और एक भतीजी का विवाहित होना आदि को ध्यान में रखते हुए जल्द ही मामले पर विचार किया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि हर मामले में बच्चों की इच्छा जानना अनिवार्य नहीं है। वर्तमान मामले में, निचली अदालत ने 1890 के अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों पर विचार किया और बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए बुलाना अनुचित समझा। उन्होंने आगे दलील दी कि किसी भी मामले में, बच्चों से इस अदालत द्वारा भी बातचीत की गई थी और उन दोनों ने अपनी मां के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है। इसलिए, केवल इसलिए कि बच्चों से मां को अभिरक्षा देने से पहले निचली अदालत द्वारा बातचीत नहीं की गई थी, विवादित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पिता की तुलना में प्रतिवादी-माँ आर्थिक रूप से अधिक सक्षम है और सभी मामलों में अधिक उपयुक्त है, इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने सही ढंग से यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि बच्चों के कल्याण को सर्वोपरि माना जाना चाहिए, भले ही पिता 1956 के अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राकृतिक अभिभावक है, लेकिन बच्चों की अभिरक्षा देकर माँ को अभिभावक नियुक्त करना बच्चों के हित में होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पिता को बच्चों से मिलने का अधिकार है, जिसका वह प्रयोग करेंगे। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने **श्यामराव मारोती कोरवाटे बनाम दीपक किसनराव टेकाम[8], रोक्सान शर्मा बनाम अरुण शर्मा[9] और तेजस्विनी गौड़ और अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी और अन्य[10]** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर गहनता से विचार किया है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है, साथ ही विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय का भी अवलोकन किया है, जिसमें बच्चों की अभिरक्षा प्रतिवादी-मां के पक्ष में प्रदान की गई है।

8. अभिरक्षा प्रदान करने के आदेश को चुनौती देने वाली मुख्य चुनौतियों में से एक यह है कि अपीलकर्ता-पिता प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते, जैसा कि अधिनियम 1956 की धारा 6 के तहत प्रावधान किया गया है, अधिकार के रूप में, वह बच्चों की अभिरक्षा का हकदार है और केवल तभी, जब किसी कारण से, यदि पिता मौजूद नहीं है, तो पिता के स्थान पर, बच्चों की अभिरक्षा माँ के पक्ष में दी जा सकती है। अधिनियम 1956 की धारा 6 के तहत अधिकार के दावे को इस बात पर उचित विचार किए बिना प्रभावी नहीं किया जा सकता है कि बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में, यह संक्षेप में माना गया है और अब यह स्थापित सिद्धांत बन गया है कि अभिरक्षा और संरक्षकता प्रदान करने के मामले में, सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण है। यह सच है कि धारा 6 पिता को एकमात्र अभिभावक घोषित करती है और यह केवल तभी घोषित किया गया है जब बच्चा पांच वर्ष से कम उम्र का हो, बच्चे की अभिरक्षा आमतौर पर माँ के पास होगी। लेकिन, कानून के तहत बनाया गया यह अधिकार पूर्ण नहीं है। हर बार जब पिता और माता के प्रतिस्पर्धी दावे उनके बच्चों की अभिरक्षा देने के मामले में न्यायालय के समक्ष लाए जाते हैं, तो न्यायालय का दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से पैरेंस पैट्रिया दृष्टिकोण होना चाहिए। सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण और बच्चे का सर्वोत्तम हित क्या है, न कि यह कि कानून के तहत बच्चे की अभिरक्षा लेने का बेहतर अधिकार किसके पास है। ऐसी स्थिति में, पिता के वैधानिक अधिकार को प्रभावी किया जाना चाहिए, यदि वह बच्चे के सर्वोत्तम हित में है, तो कल्याण सर्वोपरि विचार है। हालांकि, किसी दिए गए मामले में, रिकॉर्ड पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के तुलनात्मक मूल्यांकन के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बच्चे के सर्वोत्तम हित की पूर्ति होगी, यदि उन्हें मां की अभिरक्षा में रहने दिया जाए, भले ही पिता के वैधानिक अधिकार के अनुसार, जैसा कि 1956 के अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रदान किया गया है, बच्चे को मां की अभिरक्षा में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रखना न्यायालय का कर्तव्य होगा, यदि यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में है। अधिकार और कल्याण के बीच इस झगड़े में, अधिकार को हमेशा कल्याण के आगे झुकना पड़ता है।

9. **रोज़ी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल**[11] के मामले में यह माना गया कि बच्चों की अभिरक्षा को नियंत्रित करने वाला नियंत्रण विचार बच्चों का कल्याण है न कि माता-पिता का अधिकार।

10. **सुश्री गीता हरिहरन और अन्य बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य**[12] के मामले में, न्यायमूर्ति ने माना कि "पिता और उसके बाद माता" शब्दों में, 'के बाद' शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से 'जीवनपर्यन्त के बाद' नहीं है। जिस संदर्भ में यह धारा 6(ए) में दिखाई देता है, उसका अर्थ है "अनुपस्थिति में," इसमें "अनुपस्थिति" शब्द का अर्थ है पिता का किसी भी कारण से नाबालिग की संपत्ति या व्यक्ति की देखभाल से अनुपस्थित होना। यह स्पष्ट किया गया कि यदि पिता नाबालिग के मामलों के प्रति पूरी तरह से उदासीन है, भले ही वह मां के साथ रह रहा हो या यदि माता-पिता के बीच आपसी समझ के आधार पर, बाद वाले को नाबालिग की विशेष रूप से देखभाल करने के लिए रखा गया हो या यदि पिता किसी भी कारण से शारीरिक रूप से अक्षम हो, तो पिता को अनुपस्थित माना जा सकता है और मां एक मान्यता प्राप्त प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते, नाबालिग की ओर से अभिभावक के रूप में कार्य कर सकती है। अंत में, यह माना गया कि इस तरह की व्याख्या कानून को संवैधानिक सीमाओं के भीतर रखेगी अन्यथा यदि "बाद में" शब्दों का अर्थ पिता के जीवनकाल के दौरान अभिभावक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है, तो यह लैंगिक समानता के मूल सिद्धांतों में से एक का उल्लंघन होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह सिद्धांत कि बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि माना जाता है, अभिभावकत्व के वैधानिक अधिकार को कल्याण पहलू के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, पर **गौरव नागपाल** (सुप्रा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति द्वारा विस्तार से विचार किया गया,

जिसमें अंग्रेजी और अमेरिकी कानून को ध्यान में रखा गया और 1956 के अधिनियम की धारा 6 के तहत निर्धारित वैधानिक अधिकार के संदर्भ में भारत में लागू निम्नलिखित सिद्धांत और अधिनियम में निहित प्रावधानों को भी ध्यान में रखा गया, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

अंग्रेजी विधि

29. हेल्सबरी के इंग्लैंड के कानून, चौथा संस्करण, खंड 24, पैरा 511, पृष्ठ 217 पर यह कहा गया है;

जहां किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में नाबालिग की अभिरक्षा या पालन-पोषण का प्रश्न हो, तो उस प्रश्न का निर्णय करते समय न्यायालय को नाबालिग के कल्याण को प्रथम और सर्वोपरि विचार के रूप में लेना चाहिए, तथा इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि किसी अन्य दृष्टिकोण से उस अभिरक्षा या पालन-पोषण के संबंध में पिता का दावा माता के दावे से श्रेष्ठ है या माता का दावा पिता के दावे से श्रेष्ठ है।

(जोर दिया गया)

यह भी कहा गया है कि यदि नाबालिग किसी भी आयु का है, तो न्यायालय उसकी इच्छाओं को ध्यान में रखेगा। (पैरा 534; पृष्ठ 229)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. कभी-कभी नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की मांग की जाती है। ऐसे मामलों में भी, रिट-कोर्ट द्वारा ध्यान में रखा जाने वाला सर्वोपरि विचार 'बच्चे का कल्याण' है।

31. हैबियस कॉर्पस, खंड 1, पृष्ठ 581 में बेली ने कहा है;

पिता की प्रतिष्ठा क्रिस्टल की तरह बेदाग हो सकती है; वह शिशु के सामान्य कल्याण की देखरेख करने में थोड़ी सी भी मानसिक, नैतिक या शारीरिक अयोग्यता से

ग्रस्त नहीं हो सकता है; माता को बिना किसी औचित्य के बहाने के उससे अलग किया जा सकता है; और फिर भी बच्चे के हितों के लिए पिता के अधिकार को अस्वीकार करना और उसे माँ के पास जारी रखना अनिवार्य हो सकता है। उसकी कोमल उम्र और उसके स्वास्थ्य की अनिश्चित स्थिति उसकी उचित देखभाल के लिए माँ की सतर्कता को अपरिहार्य बनाती है; क्योंकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता की चिंता सबसे अच्छे विकल्प की तलाश करेगी और उसे प्राप्त करेगी, फिर भी मानवता की हर वृत्ति स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि कोई भी विकल्प उस महिला की जगह नहीं ले सकता है, जो अपने बच्चे के सोते हुए पालने या जागने के क्षणों पर निगरानी रखती है, नर्सों के वेतन के सबसे उदार भत्ते की तुलना में संभवतः गहरी और पवित्र भावना से प्रेरित होती है।

यह भी देखा गया है कि एक आकस्मिक पहलू, जिसका इस प्रश्न पर असर पड़ता है, पर भी ध्यान दिया जा सकता है। यह निर्धारित करने में कि क्या बच्चे के सर्वोत्तम हितों के लिए उसकी अभिरक्षा पिता या माता को देना होगा, न्यायालय बच्चे से उचित रूप से परामर्श कर सकता है, यदि उसके पास पर्याप्त निर्णय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

32. मैक ग्राथ, रे, (1893) 1 अध्याय 143: 62 एलजे अध्याय 208 में, लिंडले, एल.जे. ने कहा;

न्यायालय के विचार के लिए प्रमुख मामला बच्चे का कल्याण है। लेकिन बच्चे के कल्याण को सिर्फ़ पैसे या सिर्फ़ शारीरिक सुख-सुविधा से नहीं मापा जाना चाहिए। 'कल्याण' शब्द को उसके व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए। बच्चे के नैतिक या धार्मिक कल्याण के साथ-साथ उसके शारीरिक कल्याण पर भी विचार किया जाना चाहिए। न ही स्नेह के बंधन को नज़रअंदाज़ किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

अमेरिकी विधि

33. संयुक्त राज्य अमेरिका का कानून भी इससे अलग नहीं है। अमेरिकी न्यायशास्त्र, दूसरा संस्करण, खंड 39; पैरा 31; पृष्ठ 34 में कहा गया है;

एक नियम के रूप में, नाबालिग के अभिभावक के चयन में, बच्चे का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि विचार होता है, जिसके लिए कभी-कभी माता-पिता के अधिकारों को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

(जोर दिया गया)

पैरा 148; पृष्ठ 280-81 में कहा गया है;

आम तौर पर, जहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसी बच्चे की अभिरक्षा के अधिकार को निर्धारित करने के उद्देश्य से चलाई जाती है, विवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न शामिल नहीं होता है, क्योंकि एक शिशु को वयस्क होने तक किसी की अभिरक्षा में माना जाता है। न्यायालय, बाल अभिरक्षा मामले में रिट पारित करते समय, एक न्यायसंगत प्रकृति के मामले से निपटता है, यह माता-पिता या अभिभावक के किसी भी कानूनी अधिकार से बंधा नहीं है, बल्कि बच्चे की अभिरक्षा के लिए उसके दावे को मानव स्वभाव पर आधारित दावे के रूप में उचित वजन देना है और आम तौर पर न्यायसंगत और न्यायसंगत है। इसलिए, इन मामलों का फैसला याचिकाकर्ता के गैरकानूनी कारावास या अभिरक्षा से राहत पाने के कानूनी अधिकार पर नहीं किया जाता है, जैसा कि एक वयस्क के मामले में होता है, बल्कि उन लोगों के सर्वोत्तम हितों के न्यायालय के दृष्टिकोण पर होता है जिनके कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि वे किसी व्यक्ति या किसी अन्य की अभिरक्षा में रहें; और इसलिए, न्यायालय किसी बच्चे को किसी दावेदार या किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में सौंपने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, उसे अपने विवेक के अनुसार उस समय उसके कल्याण के लिए आवश्यक अभिरक्षा में छोड़ देना चाहिए। संक्षेप में, बच्चे का कल्याण सर्वोच्च विचार है, भले ही उसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माता-पिता के अधिकार और गलत कुछ भी हों, हालांकि माता-पिता के प्राकृतिक अधिकार विचार के हकदार हैं।

माता-पिता द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही के माध्यम से बच्चे की अभिरक्षा के लिए किया गया आवेदन न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है, तथा अभिरक्षा माता-पिता से तब रोकी जा सकती है, जब यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो कि ट्रस्ट के लिए अयोग्यता या अन्य पर्याप्त कारणों से अभिरक्षा में परिवर्तन से बच्चे के स्थायी हितों की बलि दी जाएगी। यह निर्धारित करने में कि क्या बच्चे के सर्वोत्तम हित में उसकी अभिरक्षा पिता या माता को देना होगा, न्यायालय बच्चे से उचित रूप से परामर्श कर सकता है, यदि उसके पास पर्याप्त निर्णय है।

(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. हावर्थ बनाम नॉर्थकॉट 152 कॉन 460: 208 ए 2nd 540: 17 एएलआर 3rd 758 में; यह कहा गया था;

"बाल अभिरक्षा का निर्धारण करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण कार्यवाही में, न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला अधिकार क्षेत्र ऐसे मामलों में अपनी अंतर्निहित न्यायसंगत शक्तियों पर आधारित होता है और अपने शिशु वार्ड की सुरक्षा के लिए पैरेंस पैट्रिया के रूप में राज्य के बल का प्रयोग करता है, और जांच की प्रकृति और दायरा तथा प्राप्त किए जाने वाले परिणाम के लिए न्याय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग आवश्यक है।"

यह भी कहा गया कि

बाल अभिरक्षा मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूपों का प्रयोग प्राचीन सामान्य कानून रिट या क़ानून द्वारा परिकल्पित कारावास या संयम की वैधता का परीक्षण करने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि इसका प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसा साधन प्रदान करना है जिसके द्वारा न्यायालय अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए यह निर्धारित कर सके कि बच्चे के कल्याण के लिए क्या सर्वोत्तम है, और निर्णय बच्चे के कल्याण में शामिल न्यायों पर

विचार करके किया जाता है, जिसके विरुद्ध माता-पिता सहित किसी के भी कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

(जोर दिया गया)

यह भी संकेत दिया गया कि आम तौर पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने का आधार अवैध अभिरक्षा है; लेकिन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा के लिए दायर की गई ऐसी रिट के मामले में कानून का संबंध अभिरक्षा की अवैधता से नहीं बल्कि बच्चे के कल्याण से है।

35. भारत में कानूनी स्थिति उपरोक्त सिद्धांत का अनुसरण करती है। ऐसे कई क़ानून हैं जो इन सुस्थापित सिद्धांतों को विधायी मान्यता देते हैं। यह उचित होगा कि हम इस स्थिति से निपटने वाले कुछ क़ानूनों की जाँच करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. संरक्षक अधिनियम, संरक्षकों और वार्डों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है। उक्त अधिनियम की धारा 4 में "नाबालिग" की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है जो वयस्क नहीं हुआ है। "संरक्षक" का अर्थ है नाबालिग के शरीर या उसकी संपत्ति या उसके शरीर और संपत्ति दोनों की देखभाल करने वाला व्यक्ति। "वार्ड" की परिभाषा ऐसे नाबालिग के रूप में की गई है जिसके शरीर या संपत्ति या दोनों के लिए कोई संरक्षक है। अध्याय II (संरक्षक अधिनियम की धारा 5 से 19) संरक्षकों की नियुक्ति और घोषणा से संबंधित है। इसकी धारा 7 संरक्षकता के संबंध में आदेश देने की न्यायालय की शक्ति से संबंधित है और इस प्रकार है:

7. संरक्षकता के संबंध में आदेश देने की न्यायालय की शक्ति (1) जहां न्यायालय संतुष्ट है कि यह नाबालिग के कल्याण के लिए है कि आदेश दिया जाना चाहिए--

(क) उसके शरीर या संपत्ति अथवा दोनों का संरक्षक नियुक्त करना, अथवा
(ख) किसी व्यक्ति को ऐसा संरक्षक घोषित करना, न्यायालय तदनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(2) इस धारा के अधीन आदेश से किसी ऐसे संरक्षक को हटाने का तात्पर्य होगा जिसे वसीयत या अन्य लिखत द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है या न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है।

(3) जहां किसी अभिभावक को वसीयत या अन्य दस्तावेज द्वारा नियुक्त किया गया है या न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया है, वहां इस धारा के तहत किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर अभिभावक नियुक्त या घोषित करने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि पूर्वोक्त रूप से नियुक्त या घोषित अभिभावक की शक्तियां इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत समाप्त नहीं हो जाती हैं।

37. अभिभावक अधिनियम की धारा 8 में संरक्षकता के संबंध में आदेश के लिए आवेदन करने के हकदार व्यक्तियों की गणना की गई है। धारा 9 अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय को संरक्षकता के लिए आवेदन पर विचार करने का अधिकार देती है। धारा 10 से 16 न्यायालय की प्रक्रिया और शक्तियों से संबंधित हैं। धारा 17 एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान है और इसे पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. संरक्षक नियुक्त करने में न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले मामले.-(1) किसी अवयस्क के संरक्षक की नियुक्ति या घोषणा करने में न्यायालय, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस बात से मार्गदर्शित होगा कि अवयस्क जिस कानून के अधीन है, उसके अनुरूप परिस्थितियों में अवयस्क के कल्याण के लिए क्या प्रतीत होता है।

(2) अवयस्क के कल्याण के लिए क्या होगा, इस पर विचार करते समय न्यायालय अवयस्क की आयु, लिंग और धर्म, प्रस्तावित संरक्षक के चरित्र और क्षमता तथा अवयस्क से उसके नातेदारों की निकटता, मृतक माता-पिता की इच्छाएं, यदि कोई हों, तथा प्रस्तावित संरक्षक के अवयस्क या उसकी संपत्ति के साथ किसी विद्यमान या पिछले संबंध को ध्यान में रखेगा।

(3) यदि नाबालिग इतना बड़ा है कि वह बुद्धिमानी से अपनी पसंद बना सके, तो न्यायालय उस पसंद पर विचार कर सकता है।

** **

(5) न्यायालय किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अभिभावक नियुक्त या घोषित नहीं करेगा।

38. धारा 19 न्यायालय को कुछ मामलों में अभिभावक नियुक्त करने से रोकती है। अध्याय III (धारा 20 से 42) अभिभावकों के कर्तव्यों, अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करता है।

39. यह अधिनियम हिंदुओं में अल्पसंख्यकता और संरक्षकता से संबंधित एक और समान रूप से महत्वपूर्ण क़ानून है। धारा 4 में "नाबालिग" की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। "संरक्षक" का अर्थ है नाबालिग के शरीर या उसकी संपत्ति या उसके शरीर और संपत्ति दोनों की देखभाल करने वाला व्यक्ति, और अन्य बातों के साथ-साथ इसमें प्राकृतिक संरक्षक भी शामिल है। अधिनियम की धारा 2 में घोषणा की गई है कि अधिनियम के प्रावधान 1890 अधिनियम के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके विरुद्ध।

40. धारा 6 में यह निर्धारित किया गया है कि किसे प्राकृतिक संरक्षक कहा जा सकता है। यह इस प्रकार है;

6. हिंदू अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक.-- हिंदू अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक, अवयस्क के शरीर के साथ-साथ उसकी संपत्ति के संबंध में (संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसके अविभाजित हित को छोड़कर) हैं--

(क) लड़के या अविवाहित लड़की के मामले में--पिता, और उसके बाद माता; बशर्ते कि पांच वर्ष की आयु पूरी न करने वाले अवयस्क की अभिरक्षा सामान्यतः माता के पास होगी;

(ख) नाजायज लड़के या नाजायज अविवाहित लड़की के मामले में--माता, और उसके बाद पिता।

(ग) विवाहित लड़की के मामले में - पति:

बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों के तहत नाबालिग के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं होगा -

(क) यदि वह हिंदू नहीं रह गया है, या

(ख) यदि उसने पूरी तरह से और अंतिम रूप से दुनिया को त्याग दिया है और एक संन्यासी (वानप्रस्थ) या एक तपस्वी (यति या संन्यासी) बन गया है।

स्पष्टीकरण.--इस धारा में, "पिता" और "माता" पदों में सौतेला पिता और सौतेली माँ शामिल नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. धारा 8 प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियों को सूचीबद्ध करती है। धारा 13 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है और नाबालिग के कल्याण से संबंधित है। इसे विस्तार से उद्धृत किया जा सकता है;

13. नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि विचार होगा - (1) किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा हिंदू नाबालिग के संरक्षक के रूप में नियुक्त या घोषित करने में, नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि विचार होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम या हिंदुओं में विवाह में संरक्षकता से संबंधित किसी कानून के प्रावधानों के आधार पर संरक्षकता का हकदार नहीं होगा, यदि न्यायालय की राय है कि उसकी संरक्षकता नाबालिग के कल्याण के लिए नहीं होगी।

(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26 बच्चों की अभिरक्षा के लिए प्रावधान करती है और घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, न्यायालय समय-समय पर ऐसे अंतरिम आदेश दे सकता है, जिन्हें वह नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा , रखरखाव और शिक्षा के संबंध में उचित और उचित समझे, जहां भी संभव हो, उनकी इच्छाओं के अनुरूप।

43. नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं। यह निर्धारित करने में कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा किसे दी जानी चाहिए, सर्वोपरि विचार 'बच्चे का कल्याण' है, न कि उस समय लागू किसी क़ानून के तहत माता-पिता के अधिकार।

44. उपर्युक्त वैधानिक प्रावधान भारत में कई मामलों में न्यायालयों के समक्ष विचारार्थ आए। आइए कुछ निर्णयों पर विचार करें, जिनमें न्यायालयों ने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा प्रदान करने से संबंधित सिद्धांतों को उनके हित और कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए लागू किया है।

45. सरस्वतीबाई श्रीपाद बनाम श्रीपाद वासनजी आईएलआर 1941 बॉम 455: एआईआर 1941 बॉम 103 में बंबई उच्च न्यायालय ने कहा; "न्यायालय के लिए न तो पिता का कल्याण और न ही माता का कल्याण सर्वोपरि है। केवल नाबालिग का कल्याण ही सर्वोपरि है।"

(जोर दिया गया)

46. रोजी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल (1973) 1 एससीसी 840 में, इस न्यायालय ने माना कि 1890 अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य केवल नाबालिग की शारीरिक अभिरक्षा नहीं है, बल्कि वार्ड के स्वास्थ्य, भरण-पोषण और शिक्षा के अधिकारों की उचित सुरक्षा है। अधिनियम के तहत न्यायालय की शक्ति और कर्तव्य नाबालिग का कल्याण है। नाबालिग के कल्याण के प्रश्न पर विचार करते समय, स्वाभाविक अभिभावक के रूप में पिता के अधिकार को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि पिता की अभिरक्षा बच्चों के कल्याण को बढ़ावा नहीं दे सकती है, तो उसे ऐसी संरक्षकता से इनकार किया जा सकता है।

47. फिर से, थ्रीटी होशी डोलिकुका बनाम होशियाम शावक्ष डोलिकुका MANU/SC/ 0149/1982 MANU/ SC/0149/1982 : [1983]1SCR49 में, इस न्यायालय ने दोहराया कि नाबालिग की अभिरक्षा के सवाल पर फैसला करने में न्यायालय का एकमात्र विचार नाबालिग का कल्याण और हित होना चाहिए। और यह न्यायालय का विशेष कर्तव्य और जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में बच्चे के लाभ और कल्याण के लिए क्या होगा, यह तय करने के लिए परिपक्व सोच वास्तव में आवश्यक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

48. केवल इसलिए कि उसकी व्यक्तिगत देखभाल और उसके बच्चों के प्रति लगाव में कोई दोष नहीं है - जो हर सामान्य माता-पिता में होता है, उसे अभिरक्षा नहीं दी जाएगी। केवल इसलिए कि पिता अपने बच्चों से प्यार करता है और अन्यथा अवांछनीय नहीं दिखाया गया है, जरूरी नहीं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि बच्चों का कल्याण उसे अभिरक्षा देने से बेहतर होगा। बच्चे न तो केवल संपत्ति हैं और न ही वे अपने माता-पिता के लिए खिलौने हैं। आधुनिक परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों में माता-पिता का अपने बच्चों के भाग्य और जीवन पर पूर्ण अधिकार मानव प्राणी के रूप में उनके कल्याण के विचारों के अधीन होना चाहिए ताकि वे समाज के उपयोगी सदस्य बनने के लिए सामान्य संतुलित तरीके से बड़े हो सकें और माता और पिता के बीच विवाद की स्थिति में अभिभावक न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह नाबालिग बच्चों के कल्याण की आवश्यकताओं और उनके ऊपर उनके संबंधित माता-पिता के अधिकारों के बीच एक न्यायोचित और उचित संतुलन बनाए।

49. सुरिंदर कौर संधू (श्रीमती) बनाम हरबक्स सिंह संधू MANU/SC/ 0184/1984 MANU/ SC/ 0184/1984 : [1984] 3SCR422 में, इस न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 6 पिता को नाबालिग पुत्र का प्राकृतिक अभिभावक बनाती है। लेकिन वह प्रावधान इस सर्वोपरि विचार को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता कि नाबालिग के कल्याण के लिए क्या अनुकूल है। [एलिज़ाबेथ दिनशॉ (श्रीमती) बनाम अरवंद एम. दिनशॉ (1987) 1 एससीसी 42; चंद्रकला मेनन (श्रीमती) बनाम विपिन मेनन (कैप्टन) भी देखें।

50. जब अदालत को माता-पिता द्वारा की गई परस्पर विरोधी मांगों का सामना करना पड़ता है, तो हर बार उसे मांगों को उचित ठहराना पड़ता है। अदालत को न केवल कानूनी आधार पर मुद्दे को देखना होता है, ऐसे मामलों में उन मुद्दों को तय करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण प्रासंगिक होते हैं। तब अदालत इस बात पर ज़ोर नहीं देती कि पक्ष क्या कहते हैं, उसे ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना होता है जिसका उद्देश्य नाबालिग का कल्याण हो। जैसा कि हाल ही में मौसमी मोइत्रा गांगुली के मामले (सुप्रा) में देखा गया है, न्यायालय को बच्चे की सामान्य संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को उचित महत्व देना चाहिए, लेकिन भौतिक सुख-सुविधाओं के अलावा नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान देना चाहिए। वे दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण नहीं तो बराबर ही हैं।

51. अधिनियम की धारा 13 में प्रयुक्त शब्द 'कल्याण' का शाब्दिक अर्थ लगाया जाना चाहिए और इसे इसके व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए। बच्चे के नैतिक और नैतिक कल्याण के साथ-साथ उसके शारीरिक कल्याण को भी न्यायालय द्वारा तौला जाना चाहिए। यद्यपि माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विशेष क़ानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा अपने पैरेंस पैट्रिया क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के रास्ते में आड़े आ सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अंजलि कपूर (एसएमटी) (सुप्रा) के मामले में एक अन्य निर्णय में भी, इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

17. "श्रीमती एलिजाबेथ दिनशॉ बनाम अरविंद एम. दिनशॉ और अन्य में। (एआईआर 1987 एससी 3) में इस न्यायालय ने कहा है कि जब भी न्यायालय के समक्ष नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो मामले का निर्णय पक्षों के कानूनी अधिकारों के आधार पर नहीं बल्कि एकमात्र और प्रमुख मानदंड के आधार पर किया जाना चाहिए कि बच्चे के हित और कल्याण के लिए सबसे अच्छा क्या होगा।

13. नील रतन कुंडू और अन्य (सुप्रा) के मामले में लागू सिद्धांत को इस प्रकार समझाया गया था:-

44. सुरिंदर कौर संधू (श्रीमती) बनाम हरबक्स सिंह संधू, (1984) 3 एससीसी 698 में इस न्यायालय ने माना कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 पिता को नाबालिग बेटे का प्राकृतिक संरक्षक बनाती है। लेकिन यह प्रावधान इस सर्वोपरि विचार को खत्म नहीं कर सकता कि नाबालिग के कल्याण के लिए क्या अनुकूल है। [एलिज़ाबेथ दिनशॉ (श्रीमती) बनाम अरवंद एम. दिनशॉ, (1987) 1 एससीसी 42; चंद्रकला मेनन (श्रीमती) बनाम विपिन मेनन (कैप्टन), (1993) 2 एससीसी 6 भी देखें]।

48. बिमला देवी बनाम सुभाष चंद्र यादव 'निराला', एआईआर 1992 पैट 76 में न्यायालय ने माना कि नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए और सामान्य नियम (पिता

प्राकृतिक अभिभावक है और इसलिए, बच्चे की अभिरक्षा का हकदार है) का पालन नहीं किया जा सकता है यदि उस पर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है। ऐसे मामले में, नाबालिग लड़की के अभिभावक के रूप में दादी की नियुक्ति कानून के विपरीत नहीं कही जा सकती। 1956 अधिनियम की धारा 13 में 'कल्याण' शब्द की उदारतापूर्वक व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा;

"8. ...यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इस धारा में प्रयुक्त 'कल्याण' शब्द को इसके व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए। बच्चे के नैतिक और नैतिक कल्याण के साथ-साथ उसके शारीरिक कल्याण को भी न्यायालय द्वारा तौला जाना चाहिए"।

(जोर दिया गया)

49. गोवर्धन लाल एवं अन्य बनाम गजेन्द्र कुमार, एआईआर 2002 राज 148 में उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सत्य है कि पिता नाबालिग बच्चे का स्वाभाविक अभिभावक होता है, इसलिए उसे अपने बेटे की अभिरक्षा का दावा करने का अधिमान्य अधिकार है, लेकिन नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में सर्वोपरि विचार नाबालिग का कल्याण है, न कि किसी विशेष पक्ष का कानूनी अधिकार। 1956 अधिनियम की धारा 6 नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए अनुकूल क्या है, इस प्रमुख विचार को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। यह भी देखा गया कि बच्चे के कल्याण को एकमात्र विचार के रूप में ध्यान में रखते हुए, बच्चे की इच्छा जानना उचित होगा कि वह किसके साथ रहना चाहता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

51. कमला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, एआईआर 1987 एचपी 34 में न्यायालय ने कहा;

"13.... न्यायालय अपने अंतर्निहित और सामान्य अधिकार क्षेत्र में बाल अभिरक्षा के मामलों का फैसला करते समय माता-पिता या अभिभावक के मात्र कानूनी अधिकार से बाध्य नहीं है। यद्यपि माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विशेष क़ानूनों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो न्यायालय को ऐसे मामलों में अपने पैरेन्स पैट्रिया अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोक सके, जिसमें बच्चे के सामान्य आराम, संतुष्टि, बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक विकास, उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामान्य रखरखाव और अनुकूल परिवेश जैसी परिस्थितियों को उचित महत्व दिया जाता है। इन मामलों का फैसला अंततः न्यायालय द्वारा बच्चे के सर्वोत्तम हितों के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, जिसके कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि वह एक माता-पिता या दूसरे की अभिरक्षा में रहे।"

नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत

52. हमारे निर्णय में, बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित कानून काफी हद तक स्थापित है और यह है। नाबालिग की अभिरक्षा के रूप में एक कठिन और जटिल प्रश्न का फैसला करते समय, न्यायालय को संबंधित क़ानूनों और उनसे प्राप्त अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ऐसे मामलों का फैसला केवल कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करके नहीं किया जा सकता। यह एक मानवीय समस्या है और इसे मानवीय स्पर्श के साथ हल किया जाना चाहिए। अभिरक्षा के मामलों से निपटने के दौरान न्यायालय न तो क़ानूनों से बंधा होता है, न ही साक्ष्य या प्रक्रिया के सख्त नियमों से और न ही मिसालों से। नाबालिग के लिए उचित अभिभावक का चयन करते समय, बच्चे के कल्याण और भलाई को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। अभिभावक का चयन करते समय, न्यायालय पैरेंस पैट्रिया क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है और उससे अपेक्षा की जाती है, बल्कि बाध्य है कि वह बच्चे के सामान्य आराम, संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को उचित महत्व दे। लेकिन भौतिक सुख-सुविधाओं के अलावा, नैतिक और नैतिक मूल्यों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। वे समान रूप से, या हम कह सकते हैं, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, आवश्यक और अपरिहार्य विचार हैं। यदि नाबालिग इतना बड़ा है कि वह कोई बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय ले सके, तो न्यायालय को ऐसी वरीयता पर भी विचार करना चाहिए, हालांकि अंतिम निर्णय न्यायालय को ही लेना चाहिए कि नाबालिग के कल्याण के लिए क्या अनुकूल है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **श्यामराव मारोती कोरवाटे** (सुप्रा) के मामले में, उपरोक्त सिद्धांतों को निम्नानुसार दोहराया गया:-

14. "यद्यपि पिता नाबालिग बच्चे के संबंध में प्राकृतिक अभिभावक होता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नाबालिग का कल्याण सर्वोपरि है, क्योंकि प्रतिवादी-पिता ने अपनी पहली पत्नी कावेरी की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर विवाह कर लिया था और दूसरी शादी से एक बेटा भी है, वह एक ग्रामीण गांव में रहता है, 90 किलोमीटर की दूरी पर काम करता है और यह तथ्य कि बच्चा जन्म से ही अपने नाना और उनके परिवार के साथ था, एक तालुका केंद्र में रहता था, जहाँ बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा था, हम महसूस करते हैं कि जिला न्यायाधीश द्वारा अपीलकर्ता नाना को नाबालिग बच्चे की 12 वर्ष की आयु तक अभिभावक नियुक्त करना उचित था।"

15. **तेजस्विनी गौड़** (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के न्यायिक निर्णय में, अभिभावकों के अभिरक्षा के कानूनी अधिकार के बजाय बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि रखने के उपरोक्त सिद्धांतों को नीचे दिए अनुसार दोहराया गया:-

25. "नाबालिग बच्चे का कल्याण सर्वोपरि विचार है:- बाल अभिरक्षा के मामलों का फैसला करते समय न्यायालय केवल माता-पिता या अभिभावक के कानूनी अधिकार से बंधा नहीं

होता है। यद्यपि विशेष क़ानून के प्रावधान माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में नाबालिग का कल्याण सर्वोच्च विचार है। न्यायालय के लिए सर्वोपरि विचार बच्चे का हित और बच्चे का कल्याण होना चाहिए।"

16. आधिकारिक घोषणाओं के आलोक में, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, न कि पिता या माता या विधायी अधिनियम के तहत किसी ऐसे व्यक्ति के वैधानिक अधिकार को।

17. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा किया गया एक और महत्वपूर्ण तर्क यह है कि मामले में निर्णय लेने से पहले, विद्वान न्यायालय को बच्चे की इच्छाओं का पता लगाना चाहिए था। प्रासंगिक समय पर, जब मामला दायर किया गया था, बच्चे की आयु छह और आठ वर्ष थी। 1890 के अधिनियम की धारा 17 उन मामलों से संबंधित है जिन पर न्यायालय को अभिभावक नियुक्त करने में विचार करना चाहिए। प्रावधान इस प्रकार है:-

> 17. संरक्षक नियुक्त करने में न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले मामले - (1) किसी नाबालिग के संरक्षक की नियुक्ति या घोषणा करने में न्यायालय, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस बात से निर्देशित होगा कि नाबालिग जिस कानून के अधीन है, उसके अनुरूप परिस्थितियों में नाबालिग के कल्याण के लिए क्या प्रतीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) नाबालिग के कल्याण के लिए क्या होगा, इस पर विचार करते समय न्यायालय नाबालिग की आयु, लिंग और धर्म, प्रस्तावित अभिभावक के चरित्र और क्षमता और नाबालिग से उसके परिजनों की निकटता, मृतक माता-पिता की इच्छाएं, यदि कोई हों, और प्रस्तावित अभिभावक के नाबालिग या उसकी संपत्ति के साथ किसी मौजूदा या पिछले संबंध को ध्यान में रखेगा।

(3) यदि नाबालिग बुद्धिमानी से वरीयता बनाने के लिए पर्याप्त उम्र का है, तो न्यायालय उस वरीयता पर विचार कर सकता है।
****

(5) न्यायालय किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अभिभावक नियुक्त या घोषित नहीं करेगा।

जबकि उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि सर्वमान्य सिद्धांत कि नाबालिग का कल्याण ही मार्गदर्शक कारक होगा, को शामिल किया गया है। उपधारा (2) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय नाबालिग की आयु, लिंग और धर्म तथा प्रस्तावित

अभिभावक के चरित्र और क्षमता और नाबालिग से उसके परिजनों की निकटता, मृतक माता-पिता की इच्छा, यदि कोई हो, तथा प्रस्तावित अभिभावक के नाबालिग या उसकी संपत्ति के साथ किसी मौजूदा या पिछले संबंध को ध्यान में रखेगा। उपधारा (3) में आगे यह दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं कि यदि नाबालिग बुद्धिमानी से वरीयता बनाने के लिए पर्याप्त उम्र का है, तो न्यायालय उस वरीयता पर विचार कर सकता है। उपधारा (5) में कहा गया है कि न्यायालय किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अभिभावक नियुक्त या घोषित नहीं करेगा।

18. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि धारा 17 में शामिल विभिन्न विचारों में से एक विचार यह है कि न्यायालय वरीयता पर विचार कर सकता है बशर्ते कि नाबालिग बुद्धिमानीपूर्ण वरीयता बनाने के लिए पर्याप्त वयस्क हो।

19. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **शीला बी. दास** (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया, उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिग की इच्छा जानना उचित माना है। इस संबंध में **नील रतन कुंडू और अन्य** (सुप्रा) के मामले में दिए गए एक अन्य निर्णय का हवाला पहले ही दिया जा चुका है, जिसमें अधिनियम 1890 की धारा 17(3) के तहत बच्चे की इच्छा जानने के लिए उसके साथ बातचीत करने की प्रासंगिकता और महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. धारा 17 के तहत दिए गए प्रावधान में व्यापक रूप से संरक्षक नियुक्त करने में न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों का प्रावधान है। इनमें से एक प्रावधान यह है कि न्यायालय नाबालिग की वरीयता पर भी विचार कर सकता है। हालांकि, चेतावनी यह है कि नाबालिग को बुद्धिमानी से वरीयता बनाने के लिए पर्याप्त उम्र का होना चाहिए। सामान्यतः, वैधानिक आदेश का पालन किया जाना चाहिए और जब तक कि नाबालिग बहुत छोटा न हो, न्यायालय द्वारा हमेशा बच्चे के साथ बातचीत करने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि उसकी इच्छाओं का पता लगाया जा सके, लेकिन केवल तभी जब यह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए कि नाबालिग बड़ा है और बुद्धिमानी से अपनी पसंद बना सकता है। वर्तमान मामले में, बच्चे छह और आठ वर्ष के हैं। आदर्श रूप से, विद्वान कुटुम्ब न्यायालय को बच्चों के साथ बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन तब, यह आवश्यक नहीं है कि हर मामले में, केवल उस आधार पर, तकनीकी उल्लंघन के आधार पर अभिरक्षा के आदेश में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए, यदि अपीलीय कार्यवाही के दौरान बच्चे की इच्छाओं का पता लगाया गया है और बच्चे की इच्छा उस पक्ष के साथ है, जिसके पक्ष में न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, रिकॉर्ड पर स्थिति यह है कि नाबालिग बच्चों से हमने चैंबर में बातचीत की थी और हम संतुष्ट हैं कि बच्चों के साथ बातचीत करने के बाद वे पिता के साथ जाने के बजाय अपनी मां के साथ रहने के इच्छुक हैं। यह बातचीत हमने पक्षों के संबंधित वकीलों की मौजूदगी में की थी।

इसलिए, केवल इस आधार पर कि निचली अदालत ने 1890 के अधिनियम की धारा 17(3) के तहत निहित प्रावधान के अनुसार बच्चों की इच्छाओं का पता लगाने में, हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, हम यह मानने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि पारिवारिक न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित के संबंध में न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचने के लिए सभी उपाय करें। इसलिए, पैरेंस पैट्रिया दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि कुटुम्ब न्यायालय को हमेशा बच्चे की इच्छाओं, उनके भावनात्मक बंधन, इच्छाओं, कठिनाइयों और भावनात्मक बाधाओं का पता लगाने के लिए बच्चे के साथ बातचीत करने का प्रयास करना चाहिए। यह केवल न्यायालय को अभिभावक की नियुक्ति के मामले में न्यायसंगत और उचित निर्णय पर पहुंचने में मदद करेगा, जो बच्चे के हित में सबसे अच्छा है।

21. पिता और माता दोनों द्वारा अपने बच्चों की देखभाल, विशेष रूप से उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं और उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाकर उनकी पढ़ाई के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के संबंध में दोनों पक्षों द्वारा बहुत तर्क दिए गए हैं। इस पहलू पर, दोनों पक्षों के साक्ष्य से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि माता-पिता, चाहे वह पिता हो या माता, अपने बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के बारे में चिंतित हैं। हालांकि, निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला है कि पिता की तुलना में बच्चों का सर्वोत्तम हित और कल्याण बेहतर होगा, यदि उन्हें मां के संरक्षण में रखा जाए। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, निचली अदालत ने मां की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा है, जो पिता की तुलना में बेहतर है। यह सच है कि हमारे सामने रखे गए कई निर्णयों के मद्देनजर, वित्तीय रूप से श्रेष्ठता एकमात्र मानदंड नहीं हो सकती है, फिर भी, यह अभिभावक की नियुक्ति से संबंधित मामले को तय करने में विचारों में से एक है। साक्ष्य आया है और अपीलकर्ता ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि वह नौकरी करता है और 8,000/- रुपये प्रतिमाह कमाता है। इसके विपरीत, अपीलकर्ता का साक्ष्य है कि वह दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करता है और 3,000/- रुपये से 4,000/- रुपये प्रतिमाह कमाता है। निचली अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि पिता की तुलना में माँ अधिक शिक्षित है। इस पहलू पर, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य निचली अदालत के निष्कर्ष को उचित ठहराते हैं। अदालत के दिमाग में एक महत्वपूर्ण विचार यह था कि माँ के घर का माहौल नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए अधिक अनुकूल और भावनात्मक रूप से आरामदायक है। रिकॉर्ड पर आए साक्ष्य और अपीलकर्ता के साक्ष्य में पहले से ही स्वीकार किया गया है कि उसकी माँ वृद्ध है और उसके बड़े भाई का अपनी पत्नी के साथ विवाद है और वह घर छोड़कर चली गई है। एक भतीजी है, जिसकी शादी भी जल्द ही होने वाली है और अगर हम बच्चों की अपनी माँ के साथ रहने की तुलना करें, तो निश्चित रूप से बच्चों को माँ की देखरेख में रखना बेहतर होगा और निश्चित रूप से उन्हें एक बूढ़ी महिला के साथ घर में रहने की तुलना में बेहतर मानसिक आराम और देखभाल प्रदान करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर जाते हैं, अंतिम विश्लेषण में, माँ निश्चित रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी आवश्यक चीजें प्रदान करने की बेहतर स्थिति में होगी। आखिरकार बच्चों के कल्याण का सर्वोपरि विचार, न्यायालयों के लिए मार्गदर्शक शक्ति है। हम **धनवंती जोशी** (सुप्रा) के मामले में अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

> 22. अब हम उस बिंदु पर विचार करेंगे जो वर्तमान कार्यवाही में कुटुम्ब न्यायालय और उच्च न्यायालय में एकमात्र अपील की गई थी, अर्थात् प्रतिवादी आर्थिक रूप से संपन्न है और बच्चे की बेहतर देखभाल कर सकता है और उसे बेहतर शिक्षा दे सकता है। लिंडले, एल.जे. ने रे. बनाम मैकग्राथ (शिशु) 1893 (1) अध्याय 143 (148) में कहा कि: "...बच्चे के कल्याण को केवल धन या केवल शारीरिक सुख-सुविधा से नहीं मापा जाना चाहिए। 'कल्याण' शब्द को इसके व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए। नैतिक और धार्मिक कल्याण के साथ-साथ उसके शारीरिक कल्याण पर भी विचार किया जाना चाहिए। न ही स्नेह के बंधनों की उपेक्षा की जा सकती है।"
>
> 23. भौतिक विचारों की "द्वितीयक" प्रकृति के बारे में, न्यूजीलैंड न्यायालय के न्यायाधीश हार्डी बॉयज़ ने वॉकर बनाम वॉकर और हैरिसन (देखें 1981 एन.जेड. हाल ही का कानून 257) (ब्रिटिश विधि आयोग द्वारा उद्धृत, कार्य पत्र संख्या 96) में कहा, "कल्याण एक सर्वव्यापी शब्द है। इसमें भौतिक कल्याण शामिल है, दोनों ही अर्थों में एक सुखद घर और एक आरामदायक जीवन स्तर प्रदान करने के लिए संसाधनों की पर्याप्तता और यह सुनिश्चित करने के लिए देखभाल की पर्याप्तता के अर्थ में कि अच्छा स्वास्थ्य और उचित व्यक्तिगत गौरव बनाए रखा जाता है। हालाँकि, भौतिक विचारों का अपना स्थान है, लेकिन वे गौण मामले हैं। अधिक महत्वपूर्ण हैं स्थिरता और सुरक्षा, प्यार और समझदारी से भरी देखभाल और मार्गदर्शन, गर्मजोशी और करुणामय संबंध, जो बच्चे के अपने चरित्र, व्यक्तित्व और प्रतिभाओं के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं"

22. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों में से एक यह है कि निचली अदालत ने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित कारण नहीं बताए हैं और साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया गया है, बल्कि केवल साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। निचली अदालत के निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, हम इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते। निचली अदालत ने सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया है, साक्ष्य, स्वीकारोक्ति, विरोधाभासों और गवाहों द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जो कुछ भी कहा गया है, उसकी जांच की है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के तहत निहित प्रावधानों के संदर्भ में निर्णय दर्ज करने के लिए निर्णय में कोई कारण नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों में से एक यह था कि परीक्षण के दौरान, अपीलकर्ता ने रिकॉर्ड पर और अधिक साक्ष्य लाने का इरादा किया था, हालांकि, बाद के चरण में, इसे उचित विचार के बिना खारिज कर दिया गया था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, न्याय के हित में, यह देखते हुए कि मामला बच्चों के संरक्षक की नियुक्ति से संबंधित है, ऐसे अतिरिक्त साक्ष्य को यांत्रिक रूप से खारिज करने के बजाय स्वीकार किया जाना चाहिए।

24. आवेदन की विषय-वस्तु और अभिलेख पर लाए जाने वाले भौतिक साक्ष्य को देखने के बाद, हमारी राय में, अपीलकर्ता के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। सभी प्रासंगिक पहलुओं पर, संतुलन पिता की बजाय माता की ओर झुकता है। हमने बच्चों की इच्छाओं का पता लगाने के लिए उनसे भी बातचीत की। हमारी सुविचारित राय में, हम ऐसे आधारों पर विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

25. परिणामस्वरूप, हमें न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और डिक्री में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला। अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज किया जाता है। तदनुसार अपील डिक्री तैयार की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-	**सही/-**
(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव)	**(विमला सिंह कपूर)**
जज	**जज**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**